ईडी के डिप्टी डायरैक्टर निरंजन सिंह ने वापिस लिया इस्तीफा

जालंधर, 12 अक्टूबर (ए)। मजीठिया केस और भोला ड्रग रैकेट की जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरैक्टर निरंजन सिंह ने अपना इस्तीफा वापिस ले लिया। उल्लेखनीय है कि निरंजन सिंह ने विभाग की कारगुजारी से नाराजगी के चलते पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। निरंजन सिंह ने इस्तीफे में लिखा था कि वह अपने निजी कारणों से नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। डिप्टी डायरैक्टर ने अपना लिखित इस्तीफा ईडी दफ्तर के प्रमुख गिरीश बाली को सौंप दिया था। हालांकि इस्तीफे में यह साफ नहीं किया गया था कि आखिरकार इस्तीफा देने की वजह क्या है। निरंजन सिंह वही अफसर हैं, जिन्होंने भोला ड्रग रैकेट मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ की थी। निरंजन सिंह ने गत सप्ताह मोहाली की अदालत में कहा था कि मजीठिया ने पूछताछ के दौरान पूरा सहयोग नहीं दिया था। साल 2015 की शुरुआत में इस केस में मजीठिया की जांच के दौरान निरंजन सिंह का तबादला जालंधर से कोलकाता कर दिया गया था। उनके तबादले का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचने पर अदालत ने उनके तबादले पर रोक लगा दी थी। साथ ही इस केस के जांच अधिकारी के तौर पर भी उन्हें बरकरार रखने के आदेश दिए गए थे। साल 2016 में निरंजन सिंह इन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट के डिप्टी डायरैक्टर पदोन्नत हुए थे। वर्णनीय है कि निरंजन सिंह का अभी तीन साल का कार्यकाल बाकी था लेकिन उनके इस्तीफे के फैसले ने कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं।

अंबिका सोनी ने किया मी टू का समर्थन, राहुल बोले- बहुत बड़ा मुद्दा

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने मी टू अभियान का समर्थन किया और कहा कि इससे महिलाओं को यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर बोलने की हिम्मत मिलेगी। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभियान को बहुत बड़ा मुद्दा करार दिया। गांधी ने केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जवाब नहीं दिया और कहा कि वह बाद में जवाब देंगे। उन्होंने राफेल मुद्दे पर बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा, मी टू एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं उस मुद्दे पर बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलूंगा। मैं अपना व्यापक मत दूंगा। सोनी ने भी अकबर के बारे में बोलने से मना कर दिया और कहा कि वह अपना मत समूचे मुद्दे पर देना चाहती हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत मामलों के बारे में नहीं बोलना चाहती क्योंकि मैं शामिल लोगों और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पर्याप्त रूप से नहीं जानती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अकबर के मुद्दे पर रिपोर्टर के सवाल का जवाब नहीं देने के बारे में कांग्रेस नेता ने कहा, वह (स्वराज) हर विषय पर बहुत अच्छी तरह दृढ़ीत करती हैं। उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया है, मैं कुछ नहीं कह सकती।

शिवसेना ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर अकबर को पद से हटाने की मांग की

मुंबई, 12 अक्टूबर (ए)।भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने कई महिला पत्रकारों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाने के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर को पद से हटाने की मांग की। शिवसेना ने गुरुवार को यह भी कहा कि अकबर के खिलाफ लगे आरोपों की गहराई से जांच की जानी चाहिए। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायांदे ने कहा, 'जहां तक मुझे पता है, पांच से छह महिला पेशेवरों ने एम जे अकबर के हाथों यौन उत्पीड़न का शिकार होने की खुलकर बात की है। घटनाओं के ब्यौरे चिंताजनक और गंभीर हैं। इसलिए मैं उन्हें तत्काल पद से हटाने की मांग करती हूं।' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' की बातें करते हैं। इसलिए अपनी छवि बनाए रखने के लिए मोदी को अकबर को उनके पद से हटा देना चाहिए।' शिवसेना की विधान पार्षद ने कहा, 'उनके खिलाफ लगे आरोपों की उचित जांच की जाए। अगर वह पाक-साफ साबित होते हैं तो उन्हें दोबारा कैबिनेट में जगह दी जा सकती है।' उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह अपना काम सही से नहीं कर रहा है। कायांदे ने कहा, 'आयोग की प्रमुख भाजपा की पुरानी सदस्य हैं।

तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की पत्नी भाजपा में शामिल

हैदराबाद, 12 अक्टूबर (ए)। तेलंगाना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी. दामोदर राजनरसिम्हा की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता पद्मिनी रेड्डी गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गईं। राजनरसिम्हा अविभाजित आंध्रप्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी के मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री थे। भाजपा में पद्मिनी रेड्डी का स्वागत करते हुए राज्य इकाई के अध्यक्ष के. लक्ष्मण ने कहा कि मेडक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों और महिलाओं के बीच कार्यों के माध्यम से उन्होंने काफी ख्याति अर्जित की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक ऐसी महिला को देश का रक्षा मंत्री (निर्मला सीतारमण) बनाया है जिनकी शादी तेलुगु परिवार में हुई है और उन्होंने एक अन्य महिला को लोकसभा अध्यक्ष (सुमित्रा महाजन) बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पद्मिनी रेड्डी राजग सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना करती हैं इसलिए वह पार्टी में शामिल हुई हैं।

कोलंबिया में मिट्टी धंसने की घटना में 12 की मौत

बोगोटा, 12 अक्टूबर (ए)। कोलंबिया में मिट्टी धंसने की घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। आपदा अधिकारियों ने बताया कि मध्य कोलंबिया के मरकेटालिया शहर में तड़के दो बजे के करीब मिट्टी धंसने की घटना हुई जिसमें पीड़ित दब गये। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त पीड़ित सो रहे थे। मिट्टी धंसने की घटना में चार बच्चों की मौत हो गई और 53 लोगों को बचा लिया गया। कोलंबिया में हर साल भारी बारिश के बाद बाढ़ आने और मिट्टी धंसने की घटना में दर्जनों लोगों की मौत होती है।

आईएसआई पर बयान को लेकर पाकिस्तान के हाईकोर्ट के जज बर्खास्त

इस्लामाबाद, 12 अक्टूबर (ए)। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने वृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को बर्खास्त कर दिया। उससे पहले एक उच्च-स्तरीय संवैधानिक निकाय ने देश की प्रभावशाली खुफिया न्यायमूर्ति शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने की सिफारिश की थी, जो आईएसआई को निशाना बनाने वाले अपने विवादित भाषण को लेकर कथित कदाचार के आरोप का सामना कर रहे थे।

कांग्रेस का नेताओं को फरमान-फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम, विमान से नहीं रेल से करें सफर

नईदिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। 2019 के लिए चुनावी मैदान तैयार है और सभी विपक्षी पार्टियों ने भी जंग में उतरने के लिए कमर कस ली है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने नेताओं को फिजूलखर्ची पर कड़ी हिदायत दी है। दरअसल कांग्रेस इन दिनों फंड के अकाल से जूझ रही है और ऐसे में नेताओं द्वारा फिजूलखर्ची से पार्टी परेशान है। पार्टी हेडक्वार्टर से नेताओं के लिए फरमान जारी हुआ है, जिसमें हिदायत दी गई है कि सभी समझदारी से ही पैसा खर्च करें। इतना ही नहीं हाईकमान नेताओं के ट्रैवल और अन्य एलाउंस पर कैंची चलाने के मूड में है। 9 अक्टूबर को पार्टी हेडक्वार्टर से नेताओं को खत लिखा गया है कि वे फ्लाइट की जगह रेल में सफर करने को तव्वजो दें। 1400 किलोमीटर के सफर के लिए सचिवों को रेल का किराया मिलेगा, विमान का नहीं। अगर कोई नेता 1400 किलोमीटर से अधिक का सफर करता है तो उसे विमान का किराया दिया जाएगा लेकिन वो भी महीने में बस दो बार। साथ में यह भी कहा गया कि अगर रेल का किराया हवाई सफर से ज्यादा है तो वे फ्लाइट से

सफर कर सकते हैं लेकिन इसका पूरा ब्यौरा पहले हेडक्वार्टर को देना होगा।

चाय-पानी में भी कटौती : नेताओं के फिजूलखर्ची से परेशान पार्टी ने उनकी कैंटीन में चाय-पानी के खर्चे पर भी कटौती करने को कहा है। चुनावी सीजन होने के चलते कार्यालय में इन दिनों कार्यकर्त्ताओं की भीड़ काफी है जिसके चलते पार्टी पर खाने-पीने का भारी बिल बन रहा है। पार्टी नहीं चाहती कि चाय-पानी पर अधिक खर्च किया जाए।

बिजली-स्टेशनरी पर खर्च कम करने को कहा : कांग्रेस ने सभी पदाधिकारियों से उनके दफ्तरों में बिजली की बचत करने की सलाह दी है ताकि बिल ज्यादा न आए। साथ ही समाचार पत्रों और स्टेशनरी जैसे सामानों पर भी कम खर्च करने को कहा गया है। पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि ऑफिस में एक ऐसा स्टॉप रखा जाए जो इन फिजूलखर्चियों पर ध्यान रखे। कंप्यूटर और बाकी उपकरणों का तभी प्रयोग किया जाए जब बहुत जरूरत हो। यह निर्देश पार्टी के सभी महासचिव, प्रभारियों, फ्रंटल संगठन के प्रमुख को भेजी गई चिट्ठी में दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई दफ्तर में गैरमौजूद है तो बिजली से चलने वाले सारे उपकरण बंद रख जाएं। साथ में यह भी कहा गया है कि नेता अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और दिल्ली में दर्शन कम दें ताकि गाड़ियों का कम उपयोग हो और पेट्रोल-डीजल पर अधिक खर्च न करना पड़े। इतना ही नहीं जो महासचिव सांसद हैं, उनको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने पिछले महीने सब राज्य इकाइयों से फंड इकट्ठा करने को कहा था।

घूस लेने के मामले में यूपी और पंजाब सबसे आगे, दिल्ली भी कुछ कम नहीं

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और लोकल सर्कल्स द्वारा कराए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में पाया गया कि संपत्ति पंजीकरण, पुलिस और नागरपालिका निगम देश की सबसे भ्रष्ट संस्थाएं हैं। सर्वे के मुताबिक 2018 में 56 फीसद लोगों को सरकारी कार्यालयों में काम कराने के लिए घूस देनी पड़ी। 2017 में यह आंकड़ा 45 फीसद था। यानी कि एक साल में घूस देने के मामले में 11 फीसद की रिकार्ड वृद्धि हुई है। भारत के 215 जिलों में पचास हजार नागरिकों द्वारा दी गई 1.60 लाख से अधिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया है। इसमें 33 फीसद महिलाओं की और 67 फीसद पुरुषों की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। 45 फीसद लोग मेट्रो शहरों से, 34 फीसद द्वितीय श्रेणी के शहर से और फीसद तृतीय श्रेणी के शहरों से शामिल किए गए हैं। 79 फीसद लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले बाबू सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में यह आंकड़ा 56फीसद और मध्य प्रदेश में 50 फीसद रहा। राजधानी दिल्ली भी नहीं है पीछे सर्वे के मुताबिक 46 फीसद लोगों का कहना है कि उन्हें पिछले एक साल में दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में काम कराने के लिए घूस देनी पड़ी। भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2018 नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि 91 फीसद लोगों को पता नहीं है कि उनकी राज्य सरकारों के पास भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर है। वहीं 82 फीसद लोगों का कहना है कि उनके स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार ने पिछले एक साल में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है।

सरकार का दावा, मौत से कुछ घंटे पहले मान ली गई थीं प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की कुछ मांगें

नईदिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। गंगा नदी के संरक्षण को लेकर पिछले 111 दिनों से अनशन कर रहे जाने-माने पर्यावरणविद प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल उर्फ स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद (86) का गुरुवार दोपहर दिल्ली का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ऋषिकेश स्थित एम्स के निदेशक डॉ. रविकांत ने बताया कि स्वामी सानंद ने गुरुवार को यहां संस्थान में अंतिम सांस ली। उन्होंने बताया कि स्वामी सानंद ने अपना शरीर एम्स ऋषिकेश के चिकित्सा शिक्षा के छात्रों के उपयोग के लिए दान कर दिया था। उन्होंने बताया कि स्वामी सानंद को उच्च रक्तचाप, हर्निया के साथ-साथ कोरोनरी आर्टरी रोग भी था और अनशन के कारण उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई थी। हरिद्वार स्थित मातृ सदन में पिछले 22 जून से अनशन कर रहे स्वामी सानंद के बुधवार को जल त्यागने के बाद प्रशासन ने उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया था। हरिद्वार जिला प्रशासन ने उनके आश्रम परिसर के चारों ओर धारा 144 लगाकर उन्हें बुधवार को जबरन उठा कर एम्स में भर्ती करा दिया था। नदी विकास और गंगा

संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि प्रोफेसर अग्रवाल की कुछ मांगें मान ली गई थीं और सरकार की ओर से आश्वासन लेकर पहुंचे हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने उनसे अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन उन्होंने अनुरोध को ठुकरा दिया था। इस बीच, गंगा संरक्षण को लेकर स्वामी सानंद के प्राण त्यागने के बाद 'मातृसदन' के प्रमुख परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने उनके निधन को हत्या करार दिया है और उनकी मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

केजरीवाल रविवार से शुरू करेंगे घर- घर जाकर चंदा मांगने का देशव्यापी अभियान

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। आप ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चंदा जुटाने के लिए इस बार बड़ी राशि में दान पर निर्भरता से हटकर हर घर से मामूली राशि में चंदा एकत्र करने का फैसला किया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल इस अभियान की शुरुआत 14 अक्टूबर को दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से करेंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि इसमें आप के विभिन्न राज्यों से सभी सांसद, विधायक और पार्षद के अलावा पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसमें केजरीवाल कार्यकर्ताओं को बतायेंगे कि आप की इस मुहिम का मकसद जनता के बीच जाकर यह बताना है कि जो पार्टी चुनावी खर्च के लिए जिससे चंदा लेती है, बाद में उन्हीं लोगों के काम करती है। इसके तहत आप के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को बतायेंगे कि भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दल उद्योगपतियों से भारी मात्रा में चंदा लेते हैं।

टीडीपी सांसद के आंध्र प्रदेश-तेलंगाना स्थित आवास और कार्यालयों पर छापा

अमरावती, 12 अक्टूबर (ए)। आयकर विभाग ने शुक्रवार को तेलगू देशम पार्टी (तेदेपा) के राज्यसभा सदस्य सी. एम. रमेश के आंध्रप्रदेश और तेलंगाना स्थित परिसरों की तलाशी ली। सांसद ने इन छापों को 'राजनैतिक बदले' की कार्रवाई करार दिया। सूत्रों ने बताया कि रमेश के कडपा जिला स्थित पैतृक गांव येरागुंतला में उनके आवास पर छापेमारी शुक्रवार की सुबह शुरू हुई। उसी वक्त आयकर विभाग के 10 कर्मचारियों के दल ने हैदराबाद में जुबली हिल्स स्थित उनके आवास और उनकी कंपनी रित्विक प्रोजेक्ट्स के कार्यालय पर भी छापा मारा। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया, 'रमेश के आंध्रप्रदेश में कडपा जिला स्थित आवासों की तलाशी चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारी हैदराबाद में भी उनके आवास और कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। यह नियमित

बात है.... इसमें कोई महत्व की बात नहीं है।' छापों की आलोचना करते हुए तेदेपा ने कहा कि यह ''विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदला है'' क्योंकि रमेश संसद में लगातार राज्य के हितों के लिए आवाज उठा रहे थे। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एन. लोकेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया, 'यह आंध्र के लोगों पर हमला है। मोदी सरकार प्रतिशोधपूर्ण रवैया अपना रही है क्योंकि हम आंध्रप्रदेश से किए गए सभी वादों को पूरा करने की मांग कर रहे थे।' उन्होंने आरोप लगाया कि इस छापेमारी का लक्ष्य उद्योगपतियों को डरा कर राज्य में निवेश की आवक को रोकना है। नयी दिल्ली में मौजूद रमेश का कहना है कि उनके परिसरों पर हो रही आयकर की छापेमारी के पीछे विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस का हाथ है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री ने स्वयं संसद के भीतर हमें नतीजे की चेतावनी दी थी क्योंकि हम लोग राज्य के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। आयकर का छापा उस चेतावनी का नतीजा है।' संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य रमेश ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले चार साल में 200 करोड़ रुपये की आय दिखायी है।

आतंकवादी की नमाज-ए-जनाज़ा पढ़ने की कोशिश, योगी सरकार ने किया नाकाम

अलीगढ़, 12 अक्टूबर (ए)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के निष्कासित छात्र आतंकवादी मन्नान वानी की नमाज़-ए-जनाज़ा को परिसर के अंदर गुपचुप तरीके से पढ़ने की कोशिशों को एएमयू प्रशासन ने नाकाम कर दिया। एएमयू के प्रवक्ता प्रोफेसर शाफे किदवाई ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन को कल शाम खबर मिली थी कि जम्मू-कश्मीर के रहने वाले कुछ छात्र कनेडी हाल के पास एकत्र हुए हैं और वे वानी की नमाज-ए-जनाज़ा पढ़ना चाहते हैं। इस पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा स्टाफकर्मी मौके पर पहुंचे। इसी बीच, एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने हस्तक्षेप करते हुए कश्मीरी छात्रों को यह

नमाज पढ़ने से रोका। उन्होंने बताया कि छात्र संघ नेताओं ने कहा कि एक आतंकवादी के जनाजे की नमाज पढ़ना स्वीकार्य नहीं है और कश्मीरी छात्रों को ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। एएमयू सुरक्षा स्टाफ ने भी उन्हें रोका। इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई, लेकिन कुछ देर बाद कश्मीरी छात्र वहां से चले गये। किदवाई ने कहा कि एएमयू प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि वह किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि अवैध तरीके से भीड़ जमा करने के आरोप में विश्वविद्यालय के तीन छात्रों को निलम्बित कर दिया गया है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने कहा कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायत करते हैं लेकिन राष्ट्रद्रोह या आतंकवाद किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दों के समर्थन का कोई भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच, अलीगढ़ से भाजपा के सांसद सतीश गौतम ने आतंकवादी अब्दुल मन्नान वानी की नमाज-ए-जनाजा पढ़ने की कोशिश करने वाले छात्रों को एएमयू से निष्कासित करने की मांग की है। हालांकि उन्होंने वह नमाज पढ़ने से रोकने के लिये एएमयू छात्र संघ की सराहना भी की।

हाईकोर्ट का आप सरकार को झटका, दिल्लीवासियों को अस्पताल में नहीं मिलेगी प्राथमिकता

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने राजधानी के गुरु तेगबहादुर अस्पताल में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को अन्य लोगों के मुकाबले तरजीह देने संबंधी आप सरकार के परिपत्र को शुक्रवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने दिल्ली की आम आदमी सरकार की इस पायलट परियोजना को चुनौती देने वाली एक एनजीओ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत इसपर विचार कर रही थी कि अन्य लोगों के मुकाबले जीटीबी में इलाज के लिए दिल्लीवासियों को तरजीह देने की आप सरकार की योजना संविधान प्रदत्त समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है या

नहीं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का आदेश मनमाना और तर्कहीन है। दिल्ली देश की राजधानी है और देश के किसी भी मरीज को यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता। यह संवैधानिक समानता के अधिकार और जीने के हक के खिलाफ है। इसीलिए हम इसे रद्द कर रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के इस तर्क को माना कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले ज्यादातर मरीज गरीब होते हैं और सरकारी अस्पताल इनके लिए आखिरी विकल्प होते हैं।

आत्महत्या रोकने के लिए ब्रिटेन में पहली बार मंत्री नियुक्त

लंदन, 12 अक्टूबर (ए)। ब्रिटेन में आत्महत्या के मामलों पर लगाम कसने के लिए पहली बार एक मंत्री की नियुक्ति की गई है। यह कदम विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर उठाया गया है। इस देश में हर साल करीब 4,500 लोग अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेते हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जैकी डॉयल प्राइस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इससे आत्महत्या के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।मे ने एक बयान में बताया इससे हम उस थप्पड़ को मिटा सकते हैं जिसके चलते कई लोग चुप रह कर पीड़ा सहने के लिए बाध्य होते हैं। हम आत्महत्या रूपी

त्रासदी को रोक सकते हैं। हम हमारे बच्चों को मानसिक रूप से बेहतर माहौल प्रदान कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा ''अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों पर ही ध्यान देने की जरूरत है। न केवल हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में सेहत पर ध्यान देना जरूरी है बल्कि कक्षाओं में, कार्यस्थलों में और समुदायों में भी सेहत पर ध्यान देना आवश्यक है। नए प्रभाग का नाम ''मानसिक स्वास्थ्य, विषमताएं और आत्महत्या की रोकथाम'' है। यह प्रभाग आत्महत्या की रोकथाम संबंधी नए राष्ट्रीय प्रयास की अगुवाई करेगा। अपनी नयी भूमिका में जैकी आत्महत्या की दर कम करने तथा मदद मांगने को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के सरकार के प्रयासों पर जोर देंगी। ब्रिटेन में हर साल करीब 45,00 लोग आत्महत्या करते हैं। देश में 45 साल से कम उम्र के पुरुषों की मौत का एक प्रमुख कारण आत्महत्या है। जैकी ने कहा ''मैं समझ सकती हूं कि आत्महत्या से परिवार और समुदाय पर कितना भयावह असर पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए मैं ऐसे परिवारों से मिल चुकी हूं। मैं चाहूंगी कि अपनी नयी भूमिका का उपयोग मैं ऐसे लोगों की पीड़ा घटाने में कर सकूं।